

ट्रांसक्रिप्ट

पावर फाइनेंस कारपोरेशन का सम्मेलन हेतु आमंत्रण

कार्यक्रम की अवधि: 1 घंटा 23 मिनट 8 सेकेंड

प्रस्तावना:

संचालक: पावर फाइनेंस कारपोरेशन की ओर से सभी उपस्थिति जनों को नमस्कार। मेरे लिए यह एक सम्मान का अवसर है जहां मैं आप सभी का निवेशकों के इस सम्मेलन में हार्दिक स्वागत करता हूँ और यहां अब मैं वित्त वर्ष 2009 की चौथी तिमाही के परिणामों की घोषणा करूंगा। जैसे कि हम सभी को जानकारी है कि पावर फाइनेंस कारपोरेशन भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम क्षेत्र की एक सूचीबद्ध नवरत्न कंपनी है जो राष्ट्रीय और बॉम्बे स्टाक एक्सचेंज दोनों स्तर पर पंजीकृत हैं। वित्त पोषण, विद्युत और ऐसे वित्तीय क्षेत्रों, जो उपभोक्ताओं को न्यूनतम लागत पर अपेक्षित गुणवत्तायुक्त विद्युत उपलब्ध कराने में अर्थव्यवस्था को सक्षम बनाएंगे, में एक अग्रणी संस्थान बनने के विजन और मिशन के साथ पावर फाइनेंस कारपोरेशन वित्तीय समाधानों (उत्पादों और सेवाओं) की एक व्यापक रेंज उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्प है। पावर फाइनेंस कारपोरेशन विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं के साथ साथ मौजूदा पावर परियोजनाओं के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराता है। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं डायस पर उपस्थित गणमान्य निवेशकों का परिचय कराना चाहता हूँ। हमारे बीच सर्वप्रथम श्री सतनाम सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि.; उनके दांयी ओर श्री एम के गोयल, निदेशक, आईडी एवं ए, पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि.; उनके दांयी ओर श्री राजीव शर्मा, निदेशक, परियोजनाएं, पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि. और बांयी ओर श्री देवेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय और पावर फाइनेंस कारपोरेशन बोर्ड में सरकारी नामिति निदेशक उपस्थित हैं। श्री सतनाम सिंह हमारे समक्ष कंपनी के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत करेंगे तत्पश्चात एक प्रजेंटेशन दिया जाएगा इसके पश्चात सवाल जवाब के लिए खुला मंच उपलब्ध होगा। मैं अब श्री सतनाम सिंह को माइक सौंपता हूँ और आप सभी से यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया अपने सेलफोन को या तो “स्विच ऑफ” कर लें अथवा उसे “साइलेंट मोड” में कर लें।

श्री सतनाम सिंह: सभी को नमस्कार और आप सभी की उत्सुकता और इस रूझान के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। निश्चित रूप से आप सभी को भलीभाँति यह ज्ञात है कि पिछले वित्त वर्ष में वित्तीय बाजार का परिवेश कैसा रहा है, परंतु सही परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाए तो मेरा मानना है और जैसा कि आप सभी लोग भी जानते हैं कि किसी भी कंपनी का निष्पादन उस वातावरण पर निर्भर करता है जहां वह कंपनी अपनी गतिविधियों का प्रचालन करती है। अतः

मेरा मानना है कि मुझे यहां वित्तीय बाजार के कुछ पहलुओं पर चर्चा करनी चाहिए जिसमें हमारी कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान अपनी गतिविधियों का प्रचालन किया है।

1. सर्वप्रथम हमारी कंपनी पर भी निश्चित ही वैश्विक मंदी और मुद्रास्फिति का प्रभाव पड़ा था।
2. वित्त वर्ष की एक निश्चित अवधि के दौरान वित्तीय तरलता (Liquidity) एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था।
3. नियामकों ने कुछ प्रयास अवश्य किए जिनके परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय कंपनियों द्वारा धन उधार लेने की स्थिति को बनाए रखा। यह कहना ठीक नहीं होगा कि इससे सभी लोग प्रभावित हुए परंतु हम इस वैश्विक मंदी से अवश्य प्रभावित हुए क्योंकि एनबीएफसी होने के नाते अंतर्राष्ट्रीय बाजार से धन जुटाने में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बाद में ये बाधाएं दूर हो गईं, परंतु अंतर्राष्ट्रीय बाजार में संसाधनों की लागत में इतनी अधिक वृद्धि हो गयी थी कि हमारी जैसी कंपनियों के लिए उसे पूरा कर पाना कठिन हो गया था, यहां तक कि हमने इन कठिन परिस्थितियों में भी अपनी रेटिंग – अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से संसाधन जुटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में संप्रभु रेटिंग को यथासंभव बेहतर बनाए रखा।

इस प्रकार वातावरण पूरी तरह से घरेलू बाजार पर निर्भर करता है। घरेलू बाजार में भी प्रतिकूल परिस्थितियां मौजूद थीं। कम अवधि के लिए धनराशि जुटाने की लागत दीर्घकालीन अवधि की तुलना में अधिक थी। इसके अलावा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो एनबीएफसी के लिए नियामक निकाय है, ने हमारा लिए सुस्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं कि जहां तक निजी क्षेत्र का संबंध है, हम उनके लिए अन्य एनबीएफसी और बैंकों के लिए लागू एकपोजर मानकों को नहीं लांघ सकते हैं। अतः इस सब के परिणामस्वरूप जैसा आप सभी जानते हैं कि ब्याज दरों में वृद्धि हुई और इक्विटी बाजार कम होने के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए संसाधन जुटाना कठिन हो गया था।

इससे पहले कि मैं उन संख्याओं का उल्लेख करूंगी जिनका आंकड़ा हमने इस बातावरण में प्राप्त किया, मैं आपके साथ उन उपलब्धियों (बातों) की चर्चा करना चाहता हूँ जो हमारी कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष में प्राप्त की है। सबसे पहले हमें केपीएमजी अवसंरचना समूह द्वारा एक पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार डा. मॉटेक सिंह अहलुवालिया द्वारा प्रदान किया गया। पुरस्कार का नामकरण “सर्वाधिक प्रशंसनीय समर्थक – विद्युत” के रूप में किया गया। अन्य पुरस्कार डीआरयूएम परियोजना जिसके बारे में आप सभी को जैसा ज्ञात है कि यह हमारा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है और जिसे यूएस की सहायता से पीएफसी द्वारा संचालित किया जा रहा है मैं हमारी सहभागिता के लिए एक भारतीय विद्युत पुरस्कार के रूप दिया गया। पीएफसी और यूएस की सहायता से लगभग 25000 लोगों को प्रशिक्षित किया गया और पिछले 3 से 4 वर्ष के दौरान जब यह प्रशिक्षण जारी था तब 25000 से भी अधिक लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। हमें दलाल स्ट्रीट से भी प्रति कर्मचारी सर्वोच्च लाभ का पुरस्कार दिया गया है और इसके अलावा हमारी

कंपनी का नाम वैश्विक वित्तीय ब्रांड की सूची में भी दर्ज किया गया – विश्व की पहली एनबीएफसी जिसे अभी हाल ही में फोक्स की वैश्विक वित्तीय ब्रांड की पहली 2000 सूची में शामिल किया गया है। इस प्रकार ये कुछ ऐसी अच्छी उपलब्धियां हैं जो हमने पिछले वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त की हैं। अब यदि हम संख्या की बात करें तो निश्चित ही आपने टीवी पर उन संख्याओं को अथवा उन प्रस्तुतियों को देखा होगा जो हमारी वेबसाइट पर पहले से अपलोड कर दी गई हैं। यदि आपको याद हो पूर्ववर्ती वर्षों में हमारे वितरण की वृद्धि 2007 – 2008, 2006 – 2007 की तुलना में उस वर्ष 15 प्रतिशत वर्ष दर वर्ष हुई है। वर्ष 2007 08 की तुलना में पिछले वर्ष 2008 09 में हमने 30 प्रतिशत का लक्ष्य हासिल किया। हमारी ऋण परिसम्पत्तियों में गतवर्ष 17 प्रतिशत की तुलना में 25 प्रतिशत की वर्ष दर वर्ष वृद्धि हुई। सकल गैर निष्पादन परिसम्पत्तियों को हम नीचे लाने में विफल रहे इसके लिए 0.03 प्रतिशत की तुलना में 0.02 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया और ऋणबही में 64000 करोड़ से भी अधिक का आंकड़ा दर्शाया गया। हमारे एनआईएम और विस्तार क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष दर वर्ष एनआईएम, तिमाही वार संख्याएं आगे दर्शायी जाएंगी, हो सकता है आप उन्हें प्रजेंटेशन के रूप में देखें। वर्ष दर वर्ष एनआईएम में 10 आधार बिंदुओं की वृद्धि हुई और यह 3.74 प्रतिशत से बढ़कर 3.84 प्रतिशत हो गया और विस्तार क्षेत्र में 13 आधार बिंदुओं के साथ 2.08 प्रतिशत से 2.21 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसके परिणामस्वरूप, कर पश्चात हमारे शुद्ध लाभ में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 1207 करोड़ से बढ़कर 1355 करोड़ हो गया। यहां में इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि इस तथ्य के बावजूद भी कि सरकार ने आने वाले 3 वर्ष में विदेशी विनिमय में होने वाली हानि को समाप्त करने के लिए किसी प्रकार की छूट प्रदान की है, हमने ऐसा नहीं किया है। हमने उसी वर्ष में सम्पूर्ण विदेशी विनिमय हानि की बुकिंग की अपनी मूल नीति का अनुपालन किया है, जिसमें वह हानि होती है और हमने इस वर्ष लगभग 253 करोड़ रूपए की राशि बुक की है और लाभ में 12 प्रतिशत की वृद्धि के आंकड़ों की गणना 253 करोड़ की हानि को बुक करने के पश्चात की गई है। यदि हम उसकी गणना न करें तो कर पश्चात शुद्ध लाभ लगभग 20 प्रतिशत हुआ है। आपको जानकर यह खुशी होगी कि निबल मूल्य पर मिलने वाले लाभ में लगभग 40 आधार बिंदुओं की वृद्धि हुई है और यह बढ़कर 14.82 प्रतिशत हो गया है। यदि हम इस राष्ट्रीय विनिमय हानि की गणना न करें तो निबल मूल्य पर लाभ का प्रतिशत 14.42 पहुंच जाता है।

बहुत बार हमने इस संबंध में चर्चा की है कि वर्ष दर वर्ष मंजूरियां उपयुक्त हैं अथवा बकाया मंजूरियां जिनका वितरण किया जाना है, वे तर्कसंगत हैं। पिछली बार जब हमने पिछले वित्त वर्ष और आने वाली तिमाहियों में 69000 करोड़ रूपए की राशि मंजूर की थी तो ये आंकड़े 70000 करोड़ रूपए के संगत आंकड़ों से मेल नहीं खाते थे; बहुत विश्लेषकों ने मुझसे यह पूछा कि ऐसा क्यों है, क्या आपको किसी मंदी आशंका है? अपने जबाब में दो बातें कहीं। 1. 69000 करोड़ रूपए की राशि इसलिए शामिल है क्योंकि हमने इसकी मंजूरी प्रदान की थी, हमने 31

मार्च 18000 करोड़ रूपए के मंजूरी पत्र जारी कर दिए हैं। अतः यदि आप इसे अलग कर देते हैं, यदि आप इसे जानबूझकर 1 अप्रैल अर्थात आगामी वित्त वर्ष में लाए थे, तो इस वर्ष की मंजूरी की राशि 57000 करोड़ रूपए और 18000 करोड़ रूपए हो जाएगी और पूर्ववर्ती वर्ष की मंजूरी घटकर 51000 करोड़ रूपए हो जाएगी और आप यह भी देखेंगे कि मंजूरियों में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। अतः एक विश्लेषक के रूप में मैं यह सुझाव देना चाहूँगा कि आप उस पर ध्यान न दें और वर्ष दर वर्ष मंजूरियों पर विचार करें, परंतु परिकल्पना के उद्देश्य से तर्कसंगत बात यह है कि हमारे जैसी किसी कंपनी के लिए संभावित वृद्धि दर क्या हो सकती है और उसकी समेकित बकाया मंजूरियां कितनी हैं और वह आंकड़ा आज की तारीख में 120000 करोड़ रूपए है। यहां तक कि आप आगे भी इतनी ही मंजूरियों की कल्पना कर सकते हैं, इससे अन्य 60000 करोड़ रूपए का मार्ग प्रशस्त होगा। इस प्रकार आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि 180000 करोड़ रूपए और आगामी 3 से 4 वर्ष में उसके संवितरण के सापेक्ष हम कितनी राशि वितरित कर पाएंगे।

हम यहां आपके साथ एक बात अवश्य साझा करना चाहेंगे कि हमारी कंपनी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाली कंपनी है और पिछले वित्त वर्ष में हमने “उत्कृष्टता श्रेणी” के सभी मानदंडों को पीछे छोड़ दिया है और इस प्रकार हमें विद्युत मंत्रालय से “उत्कृष्ट” रेटिंग प्राप्त होने वाली है और हो सकता है सार्वजनिक उद्यम से भी हमें कोई पुरस्कार प्राप्त हो। पिछले वर्ष की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि आपने 21000 करोड़ रूपए की राशि का संवितरण कैसे किया, क्या आपको संसाधन जुटाने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा? हां, निश्चित ही हमें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा, परंतु हमारे ऋणदाताओं को हम पर पूरा भरोसा था। गतवर्ष हमने संवितरण के लिए लगभग 21500 करोड़ रूपए की राशि एकत्र की और ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने अगर – सितम्बर में 4100 करोड़ रूपए की राशि जारी की जो कि किसी भी निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय कारपोरेट द्वारा जारी किया गया सबसे अधिक बांड इश्यू है। निश्चित ही बाजार में तरलता के अभाव और प्रतिकूल प्रभावों के चलते हमें समस्याओं का सामना करना पड़ा, परंतु हमने सदैव इस बात को ध्यान में रखा कि अल्पकालीन अवधि के लिए धनराशि जुटाना दीर्घकालीन अवधि की तुलना में महंगा है। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे बांड का प्रतिशत पहले 9 माह में काफी ऊपर गया और बहुत विश्लेषकों ने मुझसे यह प्रश्न किया कि “क्या आप केवल यही महसूस करते हैं कि बांड ही एक विकल्प है? अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है और बैंकों के साथ संरचना और समाधान के विकल्प नहीं रहे?” मैंने जवाब दिया, “नहीं, समय अनुकूल नहीं है”। अतः चूंकि समय बांड जारी करने के लिए उपयुक्त है, हमने बांड जारी करने का विकल्प चुना है और जब बैंकों के संरचनागत सौदे करने के लिए समय अनुकूल होगा, हम उस पर विचार करेंगे और हमने ऐसा किया भी है। वित्त वर्ष 2008 –

09 की अंतिम तिमाही में हमने संरचनागत सौदे किए हैं और उस दौरान हमने कोई बांड जारी नहीं किया है।

अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं के लिए नोडल एजेंसी होने के नाते इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि वैश्विक बाधाओं के कारण अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं के बोलीदाता आगे नहीं आएंगे। परंतु हमने इन सभी अटकलों को गलत साबित कर दिया। हमने तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना को रिलायंस पावर के माध्यम से अधिनिर्णीत किया और उसके लिए हमें बहुत अच्छे रूझान प्राप्त हुए। हमें तिलैया परियोजना के लिए 5 बोलियां प्राप्त हुईं। दिशानिर्देशों के अनुसार हमने उन्हें कंपनी अधिग्रहण के लिए कुछ समय दिया है और हम उन पर कार्यवाही कर रहे हैं।

इसके अलावा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तमिलनाडु जैसे अन्य राज्यों में कार्य चल रहा है जहां अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं के लिए आरएफटी आगामी 3 से 4 माह की अवधि में जारी किए जाने हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात और उड़ीसा में दो अन्य अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं पर भी चर्चा जारी है।

एक ज्वलंत मुद्दा जो कि ज्यादातर विश्लेषक भलीभांति जानते हैं कि भारतीय विद्युत क्षेत्र में एकीकृत, तकनीकी और वाणिज्यिक हानियां बहुत अधिक हैं और इस प्रकार लंबे समय तक भारतीय विद्युत क्षेत्र के स्थायीत्व के बारे में उठाए गए प्रश्न को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इस मुद्दे की गंभीरता को समझा है और एक पुनर्गठित एपीडीआरपी स्कीम शुरू की है जिसका प्राथमिक लक्ष्य एटी और सी हानियों को 30000 से अधिक आबादी वाले कस्बों के लिए उनके वर्तमान स्तर 15 प्रतिशत से कम लाना है। हमें इस स्कीम के लिए भी नोडल एजेंसी बनाया गया है। हमें यह सेवा प्रदान करने के लिए शुल्क मिलने वाला है और स्कीम में 52000 करोड़ रूपए की राशि निहित है जिसमें से लगभग 32000 करोड़ रूपए अनुदान के रूप में प्राप्त होगा। यह वितरण कंपनियों के लिए बहुत ही आकर्षक स्कीम है। परंतु यह निष्पादन आधारित परियोजना है और कोई भी कंपनी इससे अपनी धनराशि वापस नहीं ले सकती; ऋण को अनुदान के रूप में तब तक परिवर्तित नहीं कर सकती जब तक कि इस स्कीम में उल्लिखित निष्पादन मानकों को वह पूरा नहीं कर लेती है। इस प्रकार प्रारंभ में संपूर्ण धनराशि ऋण के रूप में दी जाएगी, बाद में ऋण की 50 प्रतिशत राशि को स्थायी कटौती के आधार पर अनुदान के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा। इसके अंतर्गत न केवल एटी और सी हानियों को कम करने का लक्ष्य रखा गया है बल्कि 10:10 प्रतिशत आधार पर 5 वर्ष की अवधि के लिए इन हानियों को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है।

जैसा आप सभी को ज्ञात है कि भारतीय विद्युत क्षेत्र के संपूर्ण विकास हेतु हम सदैव सुविधाएं मुहैया कराते रहे हैं, इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमने इक्विटी पर निवेश का निश्चय

किया है, बड़ी मात्रा में नहीं बल्कि दो विद्युत विनिमय योजनाओं – भारतीय विद्युत एक्सचेंज के साथ साथ टीसीएस और एनटीपीसी द्वारा प्रोन्नत विद्युत विनिमय के लिए लघु रूप में निवेश करने का प्रस्ताव है। भारतीय विद्युत एक्सचेंज में हमारा निवेश 7 प्रतिशत और अन्य एक्सचेंज में 16.67 प्रतिशत है।

हमारे लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र आकर्षण का अन्य क्षेत्र है। हमने गतवर्ष 500 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत की है और लगभग 178 करोड़ रूपए का संवितरण किया है जो कि गतवर्ष में संवितरण की तुलना में 5 गुना है। मैंने जब से प्रभार संभाला है, आपके साथ इस बात को रखा है और हो सकता है कि आपने समाचार पत्रों में भी पढ़ा हो कि हमने नई करोबार यूनिटें सृजित करते हुए संगठन को इस उद्देश्य से पुनर्गठित किया है ताकि अतिरिक्त कारोबार जुटा सकें और अपनी वृद्धि दर को बनाए रख सकें। एक ऐसी कारोबारी यूनिट पहले एक सुविधा समूह थी जो वास्तव में पश्च एकीकरण के लिए स्थापित की गई थी, जिसका उद्देश्य कोयला खदानों, गैस पाइप लाइनों, विद्युत उपस्कर विनिर्माण आदि का वित्त पोषण है। अन्य कारोबार यूनिट जिसका मैंने पहले ही उल्लेख किया है, का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करना है। तीसरी कारोबार यूनिट का उद्देश्य विभिन्न संविदाकारों के समूह को ऋण उधार देना, चौथी यूनिट इक्विटी फंडिंग और पांचवीं यूनिट निश्चित रूप से एपीडीआरपी के लिए थी, परंतु प्रचालन संबंधी कुछ मुद्दों के कारण एपीडीआरपी यूनिट को पीएफसी के कारोबार के साथ आमेलित कर दिया गया है।

अब मैं आपको यह सूचित करना चाहूंगा कि हमने कारोबार के इन सभी क्षेत्रों अच्छी खासी प्रगति की है और वित्त वर्ष 2009-10 में जहां तक विभिन्न संविदाकारों के समूहों को धन उधार देने का प्रश्न है, तो हमने यह मूल्यांकन किया है कि हमारे पावर लेंडर क्लब में 18 बैंक, एलआईसी और हुडको शामिल हैं। हमने मूल्यांकन किया है, हमने पावर लेंडर क्लब के सदस्यों से बात की है कि विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण उधार देने की क्या संभावना है और उस मूल्यांकन के अनुसार लगभग 20000 करोड़ रूपए की राशि दिए जाने की संभावना है। जहां तक सुविधा समूह, पश्च एकीकरण का प्रश्न है, हम नए उत्पादों का विकास कर रहे हैं और ऐसी नई कंपनियों के संपर्क में हैं जो इस कारोबार में प्रवेश कर रही हैं और संभवतः दूसरी तिमाही तक हम इस नए क्षेत्र के लिए भी वास्तविक रूप से ऋण मंजूर करने में सक्षम होंगे। जहां तक नवीकरणीय ऊर्जा का प्रश्न है, हम नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को भारी मात्रा में सहायता प्रदान कर रहे हैं और इस वित्त वर्ष में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में बड़ी राशियां स्वीकृत किए जाने की संभावना है।

अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि हम अपनी उत्पादकता बनाए रखने में सक्षम रहे हैं, यह दलाल स्ट्रीट द्वारा दिए गए पुरस्कार से भी देखा जा सकता है। प्रति कर्मचारी हमारी लाभप्रदता 4 करोड़

रूप रही हैं और ऐसा कारोबार जिसका आशय प्रति कर्मचारी 180 करोड़ रूपए रहा है। हमारा कर्मचारी दल अत्यंत प्रेरित है और हम आगे भी इन उत्पादकता स्तरों को बनाए रखना चाहते हैं और जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारे कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग की सिफारिश भी जारी कर दी गई है। इससे हमारे कर्मचारी और अधिक प्रेरित होंगे और आपको यह भी पता है कि कर्मचारियों के लिए आज एक अलग नाम सार्वजनिक क्षेत्र रोजगार के रूप में बन गया है; निजी क्षेत्र में एक तरह से कुछ लाभों का हास हुआ है। अतः मुझे विश्वास है कि आगे बढ़ने से हम आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। -----

संचालक: अब हम प्रेजेंटेशन देखेंगे और तत्पश्चात सवाल – जबाब का दौर चलेगा।

प्रेजेंटेशन सत्र

प्रबंधन: सभी को नमस्कार। मैं आपके समक्ष एक छोटा सा प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करूंगा जिसमें तिमाही के साथ साथ हमारे वार्षिक आंकड़े भी दर्शाए जाएंगे। यह ठीक बात है कि हम 20 वर्ष से अधिक समय से इस कारोबार में हैं और हम सभी क्षेत्रों की परियोजनाओं का वित्त पोषण करते रहे हैं चाहे वे उत्पादन, पारेषण अथवा वितरण किसी से भी संबंधित क्यों न रही हों। हम सभी क्षेत्रों की कंपनियों जैसे केंद्रीय क्षेत्र की कंपनी, राज्य क्षेत्र की कंपनी, निजी क्षेत्र की कंपनी सभी में कारोबार करने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं और वर्तमान में हम बहुत सरकारी योजनाओं और नीतियों के कार्यान्वयन हेतु प्रमुख और नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। इन योजनाओं में अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना, पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी), ड्रम कार्यक्रम और डीडीएम कार्यक्रम शामिल हैं। वर्तमान में शीर्षस्थ 500 वित्तीय ब्रांडों की सूची में शामिल होने के साथ साथ फोब्स की वैश्विक 2000 रैंकिंग को ध्यान में रखते हुए हमने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में उच्च स्तर की दृश्यता हासिल की है। वर्ष 2006 में हमने 10000 करोड़ रूपए के संवितरण के लक्ष्य को हासिल किया था और अब वर्ष 2009 में हमने 21000 करोड़ रूपए के संवितरण का आंकड़ा पहले ही छू लिया है। वर्ष 2009 में हमने तिलैया यूएमपीपी का भी अधिनिर्णय किया है और उसके लिए रिलायंस पावर को अभिरुचि की अभिव्यक्ति हेतु पत्र (एलओआई) जारी किया है। हमारा ध्यान मुख्य रूप से भारतीय विद्युत क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में आकृष्ट रहा है। हमारे प्रमुख कारोबार के 99 प्रतिशत भाग में रूपया आवधिक ऋण, विदेशी मुद्रा ऋण, अल्पकालीन ऋण, जैसे उत्पाद विभिन्न परियोजना कंपनियों को उपलब्ध कराना शामिल हैं। हम भारतीय विद्युत

क्षेत्र को संसाधनों के वित्तीय प्रबंधन, जोखिम मूल्यांकन, दक्षता में सुधार हेतु समाधानों के रूप में परामर्श सेवाएं भी प्रदान कर रहे हैं। मानव संसाधन योजनाओं का विकास, परियोजना संभाव्यता अध्ययन, मूल रूप से हम सभी क्षेत्रों में अपना कारोबार फैला रहे हैं, चाहे अपने संगठनों का पुनर्गठन अपने निष्पादन में सुधार, जोखिम मूल्यांकन अथवा परियोजना संभाव्यता अध्ययन क्यों न हो। हमारे कारोबार की रणनीति नवीकरणीय ऊर्जा, संविदाकारों के समूहों को धन उधार देना (कंसोर्टियम लेंडिंग) जैसे क्षेत्रों पर ध्यान आकृष्ट करना होगी। हमने इसके लिए विशेष समूहों का भी गठन किया है – विद्युत उपस्कर और हमारे ईंधन संपर्क के क्षेत्र में परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए सुविधा समूह, वहीं दूसरी ओर हम अपने मौजूदा कारोबार को भी जारी रखने के लिए प्रयास करते रहेंगे। हमारी टीम में कुल 316 लोग शामिल हैं, जिसमें प्राथमिक रूप से 200 कार्यपालक और 116 गैर कार्यपालक हैं। इन 200 कार्यपालकों में से बहुत से भिन्न भिन्न व्यावसायिक पृष्ठभूमि से हैं और 40 प्रतिशत से अधिक कार्यपालकों को 15 वर्ष से भी अधिक का कार्य अनुभव प्राप्त है। हमारे प्रति कर्मचारी संवितरण आज की तारीख में 66 करोड़ के आस पास है और प्रति कर्मचारी कर पश्चात लाभ 4.3 करोड़ रूपए है, जिसके लिए भी हमें हाल ही में एक पुरस्कार दिया गया है।

यहां हम एक तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं, जहां यह बताया गया है कि स्वीकृतियों के संदर्भ में पिछले पांच वर्ष के दौरान अपने निष्पादन को हमने किस प्रकार संचालित किया है और इसके तहत हमने किन परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए मंजूरी प्रदान करने के साथ-साथ किनके लिए संवितरण किए हैं, उनके विवरण भी दिए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि वित्त वर्ष, 2005 में हमने 18500 करोड़ रूपए मूल्य की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की और अभी हाल ही में समाप्त वर्ष में हमने 57000 करोड़ रूपए के आंकड़े को छू लिया है। वित्त वर्ष 2005, जो कि लगभग 5 वर्ष पहले की बात है, के दौरान किए गए वित्त पोषण और संवितरण के संदर्भ में बात करें तो उस समय हमने 9400 करोड़ रूपए का कारोबार किया, जबकि इस वर्ष की समाप्ति हमने 21000 करोड़ रूपए के आंकड़े के साथ की है। मंजूरी की बात करें तो हमने 5 वर्ष के दौरान 28 प्रतिशत की सीएजीआर वृद्धि दर हासिल की है जबकि संवितरण की दिशा में हम 19 प्रतिशत की वृद्धि दर बनाए हुए हैं। यदि आप यह तुलना करेंगे कि हमने 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या किया और 11वीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्ष पूरे होने पर हम कहां पहुंच सके हैं, तो हमने 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1,00,000 करोड़ रूपए की परियोजनाएं स्वीकृत की हैं और 11वीं पंचवर्षीय योजना के केवल दो वर्ष में ही हमने 1,20,000 करोड़ रूपए

से अधिक राशि की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

संवितरण के संदर्भ में हमने 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 51,000 करोड़ रूपए का कारोबार किया और इस पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्ष में ही यह आंकड़ा 37,000 करोड़ रूपए तक पहुंच गया है। हमारी ऋण परिसंपत्तियों में पिछले 5 वर्ष में लगभग 29000 करोड़ रूपए से 64000 करोड़ रूपए की वृद्धि हुई है और हमने 5 वर्ष की अवधि में 21 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल की है। आज हमारा निबल मूल्य 6000 करोड़ रूपए से बढ़कर 9600 करोड़ रूपए हो गया है। इसमें वर्ष 2006-07 में आईपीओ से प्राप्त होने वाली लगभग 1000 करोड़ रूपए की राशि शामिल है। हमारी कुल आय वित्त वर्ष 2005 की तुलना में लगभग दोगुनी हो गई है और यह 3000 करोड़ रूपए से बढ़कर 6500 करोड़ रूपए के स्तर तक पहुंच गई है। हमने कुल आय के संदर्भ में पिछले 5 वर्ष के दौरान 12 प्रतिशत की सीएजीआर वृद्धि दर पंजीकृत की है। हमारे पीएटी में भी लगातार वृद्धि हो रही है और यह 5 वर्ष पहले 984 करोड़ रूपए से बढ़कर गत वर्ष की समाप्ति पर 1355 करोड़ रूपए हो गया है।

हम पिछले पांच वर्ष के दौरान 35 से 36 प्रतिशत की रेंज में लाभांश का भुगतान करते रहे हैं और वित्त वर्ष 2009 के आंकड़े केवल अंतरिम लाभांश से ही संबंधित हैं। अंतिम लाभांश अभी घोषित किया जाना है।

अब वर्तमान वर्ष के परिपेक्ष्य में जानकारी दी जा रही है: हमारे निबल लाभ में 1207 करोड़ रूपए से 1355 करोड़ रूपए की वृद्धि हुई है और इस प्रकार हमने इस मद में 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, परंतु तुलनात्मक पीएटी के संदर्भ में यदि हम कुछ समायोजनों, जो प्रेजेंटेशन के दौरान दिखाए जाएंगे, पर विचार करें तो इसमें वास्तविक रूप से 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। हमारी कुल आय एक वर्ष पहले जो 5000 करोड़ रूपए थी वह अब बढ़कर 6500 करोड़ रूपए हो गई है, इस प्रकार इस मद में भी हमने 31 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। इसी प्रकार ब्याज होने वाली निबल आय भी 1800 करोड़ रूपए से बढ़कर 2200 करोड़ रूपए हो गई है, इस प्रकार इस मद में हमने 25 प्रतिशत की वृद्धि की है। हमारी सकल एनपीए में भी एक वर्ष पहले 0.03 प्रतिशत की तुलना में 31 मार्च 2009 को समाप्त वित्त वर्ष में 0.02 प्रतिशत गिरावट दर्ज की है। वर्ष के दौरान हमारा संवितरण 21054 करोड़ रूपए रहा। हमारे निबल मूल्य में वर्ष दर वर्ष 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जहां तक वर्तमान वित्त वर्ष, पिछले वित्त वर्ष का संबंध है, हमने 1355 करोड़ रूपए का पीएटी रिपोर्ट किया था परंतु यदि आप कुछ ऐसे समायोजनों जो अनिवार्य रूप से पूर्ववर्ती अवधि के कराधान के साथ-साथ विदेशी विनिमय से ली गई उधारियों पर एमटीएम से संबंध हैं, पर विचार करें तो वर्ष 2009 के लिए हमारे पास 1470 करोड़ रूपए के पीएटी का एक तुलनात्मक आंकड़ा प्रस्तुत होगा और वर्ष 2008 के लिए यह आंकड़ा 1223 करोड़ रूपए था, इस प्रकार इसमें लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। यदि चौथी

तिमाही के लिए तिमाही आधार पर यही तुलना की जाती है तो इस दौरान हमने 391 करोड़ रूपए का पीएटी रिपोर्ट किया था, परंतु यदि हमें इन समायोजनों को पूरा करना है तो ये आंकड़े 333 करोड़ रूपए तुलना में 412 करोड़ रूपए होंगे और इस प्रकार एक बार फिर इस मद में हमने 24 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। वर्ष के दौरान हमारी ब्याज से होने वाली आय पिछले वर्ष 5000 करोड़ रूपए की तुलना में 6396 करोड़ रूपए रही, इस प्रकार इस मद में हमने 30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। हमारी अन्य आय में 66 करोड़ रूपए की राशि शामिल है जिसमें से लगभग 17 करोड़ रूपए की राशि पुनर्गठित एपीडीआरपी कार्यक्रम के अंतर्गत सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से शुल्क के रूप में प्राप्त हुई है। तिमाही के लिए कर पश्चात हमारा शुद्ध लाभ एक वर्ष पहले इसी अवधि के लिए 295 करोड़ रूपए की तुलना में 391 करोड़ रूपए रहा।

यह ऐसा आरओए वृक्ष (प्रेजेंटेशन) है जिसके माध्यम से गतवर्ष के साथ साथ तिमाही दर तिमाही आधार पर कंपनी का निष्पादन दर्शाया गया है। वर्ष के लिए हमारा प्रचालन लाभ 3.54 से बढ़कर 3.62 प्रतिशत हो गया है, अर्थात् इसमें 8 आधार बिंदुओं की वृद्धि दर्ज की गई है और यदि आप चौथी तिमाही के इन्हीं आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो वार्षिक आधार पर इसमें लगभग 23 आधार बिंदुओं की वृद्धि हुई है। परिसम्पत्तियों पर वित्तीय लाभ के संदर्भ में बात करें तो यह कर पश्चात लाभ की श्रेणी में आता है। चौथी तिमाही के दौरान यह वृद्धि 16 आधार बिंदुओं की रेंज में रही है। वर्ष 2008 09 के लिए हमारा आरओए 2.21 प्रतिशत रहा।

हमारे तुलनपत्र के संदर्भ में 31 मार्च 2009 को हमारे शेयर धारकों की निधि 10,300 करोड़ रूपए थी। एक वर्ष पहले 40000 करोड़ रूपए की तुलना में हमारी उधारी 52,000 करोड़ रूपए है। वर्तमान देनदारियां 3434 करोड़ रूपए की हैं जिसमें से लगभग 1400 करोड़ रूपए संचित न कि देय ब्याज है, इसके साथ साथ 1500 करोड़ रूपए की राशि का प्रावधान कराधान के लिए किया गया है, इस प्रकार इस मद कुल 2900 करोड़ रूपए की राशि 3434 करोड़ रूपए की राशि में मुख्य रूप से शामिल है। ऋण परिसम्पत्तियों के संदर्भ में हमने 64500 करोड़ रूपए का कारोबार किया है और इसके परिणामस्वरूप हमारी टॉप लाइन सृजित हुई हैं। हमने 34 करोड़ रूपए का निवेश भी किया है जिसमें पावर एक्सचेंज और अन्य बांडों में पीटीसी के इक्विटी शेयर शामिल हैं। हमारी कुल परिसम्पत्तियां 54700 करोड़ रूपए से बढ़कर 68000 करोड़ रूपए हो गई हैं और हमारी ऋण परिसम्पत्तियों में वर्ष दर वर्ष आधार पर 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

वर्ष के साथ साथ तिमाही के लिए मुख्य जानकारी के अंतर्गत वर्ष के दौरान हमारी उपलब्धि में 10.11 प्रतिशत से 10.92 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हमारी निधियों की लागत में भी 8.03 प्रतिशत से 8.71 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। परंतु हमारी विस्तार क्षेत्र में 0.08 प्रतिशत की तुलना में 2.21 प्रतिशत का विस्तार हुआ है, अर्थात् इस मद हमने 13 आधार बिंदुओं की वृद्धि दर्ज की

हैं। हमारे एमआईएम में भी 10 आधार बिंदुओं की वृद्धि के साथ अब यह 3.84 प्रतिशत हो गया है। 31 मार्च 2009 को प्रभावन क्षमता 6.72 प्रतिशत रही। 31 मार्च 2009 को हमारी पूंजीगत पर्याप्तता एक वर्ष पूर्व 17.20 की तुलना में 15.31 प्रतिशत रही। तिमाही सूचकांकों के संदर्भ में वर्तमान तिमाही के लिए हमारी प्रभावन क्षमता 11.2 प्रतिशत रही। तिमाही के लिए हमारी निधियों की लागत 8.78 प्रतिशत रही। तिमाही के दौरान हमारे ब्याज का विस्तार 2.10 प्रतिशत की तुलना में 2.42 प्रतिशत रहा, अर्थात् इस तिमाही के दौरान इस मद में 32 आधार बिंदुओं की वृद्धि दर्ज की गई। हमारे निबल ब्याज मार्जन में भी 3.77 प्रतिशत की तुलना में 4.04 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इस प्रकार एक बार फिर इस मद में हमने 27 आधार बिंदुओं की वृद्धि दर्ज की है।

यहां हम एक तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं जहां पिछली 8 तिमाही के दौरान मंजूरीयों और संवितरण संबंधी आंकड़े दर्शाए जाएंगे। मंजूरीयों के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि पिछली तिमाही के दौरान हमने कमाबेश स्वीकृतियों को 14000 से 15000 करोड़ रूपए की रेंज में बनाए रखा है, जबकि सामान्यतः मंजूरीयों के संबंध में हमेशा बहुत सोच विचार कर आगे बढ़ना पड़ता है क्योंकि मूलतः हमारा संगठन परियोजनाओं पर ही आधारित है। संवितरण के संदर्भ में हमने गतवर्ष, वर्ष 2007 08 के दौरान 3200 से 3300 करोड़ रूपए की रेंज में संवितरण किया है जबकि वर्ष 2008 09 में हमने 4700 से 5000 करोड़ रूपए के स्तर को हर तिमाही में बनाए रखा है। वर्ष 2009 की चौथी तिमाही के दौरान हमारा संवितरण 6954 करोड़ रूपए रहा।

अब हमारे प्रमुख संसूचकों की क्रमबद्ध तुलनात्मक जानकारी – लाल रंग की लाइन प्रभावन क्षमता दर्शाती है। यह अभी हाल ही में समाप्त हुई चौथी तिमाही के लिए 9.88 प्रतिशत से बढ़कर 11.2 प्रतिशत हो गई है। आज हमारा विस्तार वित्त वर्ष 2007 08 की पहली तिमाही में 1.93 प्रतिशत की तुलना में 2.42 प्रतिशत हो गया है। पिछली 8 तिमाही के दौरान हमारा एनआईएम 3.67 प्रतिशत से बढ़कर 4.04 प्रतिशत हो गया है। जैसा कि हमने देखा है हमारा विस्तार क्षेत्र कमोबेश 2 से लेकर 2.1 अथवा 2.2 प्रतिशत की रेंज में है। क्षेत्र में विभाजित संवितरण और स्कीमवार संवितरण के संदर्भ में वर्ष के लिए हमारा संवितरण 21054 करोड़ रूपए रहा जिसमें से 76 प्रतिशत उत्पादन क्षेत्र, 6 प्रतिशत पारेषण क्षेत्र से संबंधित है जिसकी गणना 1296 करोड़ रूपए के रूप में की गई है इसके अलावा पुनर्गठित एपीडीआरपी कार्यक्रम में 2 प्रतिशत अर्थात् 325 करोड़ रूपए की राशि शामिल है। ऋणग्राही श्रेणी के संदर्भ में हमने लगभग 70 प्रतिशत ऋण राज्य क्षेत्र, 15 प्रतिशत केंद्रीय क्षेत्र और 12 प्रतिशत संयुक्त क्षेत्र तथा 3 प्रतिशत निजी क्षेत्र को वितरित किए हैं। जहां तिमाही संख्याओं का संबंध है, हमारा तिमाही संवितरण 6954 करोड़ रहा जिसमें से लगभग 5500 करोड़ रूपए (अर्थात् 79 प्रतिशत) उत्पादन में, 348 करोड़ रूपए (अर्थात् 5 प्रतिशत) पारेषण क्षेत्र में किया गया है। संयुक्त ऋणग्राहियों के

संदर्भ में लगभग 66 प्रतिशत संवितरण राज्य क्षेत्र, 24 प्रतिशत केंद्रीय क्षेत्र, 7 प्रतिशत संयुक्त उद्यम क्षेत्र और 3 प्रतिशत निजी क्षेत्र को किया गया है।

31 मार्च 2009 को हमारा संचित संवितरण 1,13,000 करोड़ रूपए रहा। स्वीकृतियों के संदर्भ में हमने 44,600 करोड़ रूपए उत्पादन परियोजनाओं को 5800 करोड़ रूपए पारेषण परियोजनाओं को, 1500 करोड़ रूपए वितरण परियोजनाओं के लिए मंजूर किया है। ऋणग्राही श्रेणी के संदर्भ में लगभग 52 प्रतिशत की फंडिंग राज्य क्षेत्र, 32 प्रतिशत केंद्रीय क्षेत्र, 14 प्रतिशत निजी क्षेत्र के लिए की है। इस तिमाही के लिए हमारी मंजूरीयां 14,255 करोड़ रूपए रही जिसमें से 69 प्रतिशत उत्पादन, 11 प्रतिशत पारेषण 14 प्रतिशत पुनर्गठित एपीडीआरपी कार्यक्रम के अंतर्गत और 6 प्रतिशत विविध / अन्य श्रेणियों के अंतर्गत की गई। ऋणग्राहियों के संदर्भ में चौथी तिमाही के दौरान 67 प्रतिशत मंजूरीयां राज्य क्षेत्र को और 33 प्रतिशत निजी क्षेत्र को की गई। 31 मार्च 2009 को हमारी संचित मंजूरीयां 23,3978 करोड़ रूपए रहीं। ऋण परिसम्पत्तियों के संदर्भ में हमारे पास लगभग 64,421 करोड़ रूपए की सकल बकाया राशि है जिसमें से 81 प्रतिशत उत्पादन परियोजनाओं, 10 प्रतिशत पारेषण परियोजनाओं, 5 प्रतिशत वितरण परियोजनाओं और 4 प्रतिशत अन्य श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं से प्राप्त होनी हैं। संयुक्त ऋणग्राहियों के संदर्भ में लगभग हमारे ऋणों की 72 प्रतिशत राशि राज्य क्षेत्र के ऋणग्राहियों, 14 प्रतिशत केंद्रीय क्षेत्र, 7 प्रतिशत संयुक्त क्षेत्र और 7 प्रतिशत निजी क्षेत्र के ऋणग्राहियों के पास बकाया है। 31 मार्च 2009 को हमारा सकल एनपीए 13 करोड़ रूपए रहा और प्रतिशत के संदर्भ में हमारा सकल एनपीए निम्नतम स्तर अर्थात 0.02 प्रतिशत रहा। हमारे उधारी प्रोफाइल के संदर्भ में 31 मार्च 2009 को बाजार से उधार ली गई धनराशि की स्थिति इस प्रकार है – हमारी उधारी की लगभग 70 प्रतिशत राशि बांड से प्राप्त हुई है जो कि लगभग 36882 करोड़ रूपए है, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिया गया ऋण 26 प्रतिशत अर्थात 1400 करोड़ रूपए है। हमारी बकाया उधारियों की लगभग 95 प्रतिशत राशि रूपया ऋण के रूप में है। संसाधन प्रोफाइल के संदर्भ में हमारी निवेशित निधियों की 16 प्रतिशत राशि इक्विटी शेयर धारकों की निधि से आती है और लगभग 80 प्रतिशत राशि विभिन्न वित्तीय संस्थानों और धनराशि बाजारों से ली जाती है। हाइडल श्रेणी के अंतर्गत पिछले वर्ष स्वीकृत की गई विभिन्न परियोजनाओं में तिपाईंमुख जल विद्युत परियोजना मणिपुर राज्य में स्वीकृत की गई थी। यह 1500 मेगावाट क्षमता वाली परियोजना है। इस परियोजना के लिए स्वीकृत ऋण राशि 4772 करोड़ रूपए है। बेलारी थर्मल पावर स्टेशन परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित एक 500 मेगावाट क्षमता वाली परियोजना है और इसके लिए 1806 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत की गई है। ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना जिसके संदर्भ में एनएचडीसीएल के साथ कर्ज – वित्त पोषण सौदा किया गया है और इस परियोजना के लिए 1350 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत की गई है। अब तक हमारी शेयर धारिता पैटर्न के संदर्भ में प्राथमिक रूप से हम सरकारी धारिता वाली एक कंपनी हैं जिसकी 89.78 प्रतिशत शेयर धारिता भारत के राष्ट्रपति के पास होती है।

एफआईआई शेयर धारिता का प्रतिशत 4.01 है। भारतीय वित्तीय संस्थान और बैंकों के पास 1.92 प्रतिशत की धारिता है। इसके साथ ही हमारा प्रेजेंटेशन समाप्ति की ओर अग्रसर हो रहा है और तत्पश्चात प्रश्नोत्तर सत्र प्रारंभ होगा।

प्रश्नोत्तर सत्र

वक्ता नं. 1: श्रीमान जी अभी हाल ही में अखबार में एक लेख छपा था कि “एक बार फिर विद्युत की कमी महसूस की जा रही है... इसके लिए नए लक्ष्य निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है”। ऐसी स्थिति में यह स्वतः स्पष्ट है कि आपको भी रणनीति तैयार करनी होगी क्योंकि आप विद्युत से जुड़े तीनों प्रमुख क्षेत्रों की कंपनियों को वित्तीय सहायता-मुद्दे-करते-हैं-क्या आप हमारे बीच यह जानकारी दे सकते हैं कि हम किस प्रकार इस लक्ष्य को पाने में विफल रहे हैं अथवा दिग्भ्रमित हैं? चाहे राज्य क्षेत्र अथवा संयुक्त क्षेत्र अथवा निजी क्षेत्र क्यों न हो परंतु इस स्थिति में सुधार के लिए हम क्या कर सकते हैं?-----

सतनाम सिंह: हां, आप ठीक हैं, लक्ष्य से भटकने के संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। लक्ष्यों से भटकने की स्थिति योजना अवधि की समाप्ति पर निर्मित हुई थी, न कि अभी। आपके लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में स्थापित की जाने वाली लगभग 80,000 मेगावाट क्षमता के लक्ष्य की तुलना में संपूर्ण क्षमता अभिवृद्धि के लिए परियोजनाओं का अधिनिर्णय कर दिया गया है जिसका आशय... जिसे पहले दो वर्ष में ही निर्माण के लिए शून्य तिथि के रूप में जाना जाता है। वास्तव में 16 प्रतिशत क्षमता की स्थापना पहले ही कर ली गई है जो पूर्ववर्ती योजनाओं में शामिल नहीं थी। किसी प्लांट में स्थापित की जाने वाली क्षमता के अधिनिर्णय की प्रक्रिया योजना की मध्यावधि तक जारी रहती है और इस प्रकार निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए बहुत ही कम समय मिलता है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि हम जो कुछ भी योजना बनाते हैं वह साकार हो जाए, परंतु मैं कुछ घटकों के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ; एक तो यह कि इसका अधिनिर्णय पहले ही कर लिया गया है और निर्माण के लिए पर्याप्त समय है। परियोजना के आकार के आधार पर निर्माण के लिए आवश्यक औसत समय 36 से 42 माह है और इस मामले में चूंकि सभी आवश्यक क्षमता का अधिनिर्णय पहले ही कर दिया गया है अतः निर्माण के लिए 36 माह का समय उपलब्ध है। इस प्रकार अंतिम योजना में भी लक्ष्य से दूर रहने की संभावना मौजूद थी। बड़ी उत्पादन परियोजनाओं में लक्ष्य से भटकने की संभावना हमेशा रहती है क्योंकि वहां अक्सर ऐसा होता है। अन्य बात यह है कि यूनितें अथवा कुछ परियोजनाएं जिनकी 12वीं पंचवर्षीय योजना में स्थापना के लिए योजना बनाई गई थी के संबंध में उनकी स्थापना अवधि को 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में ले जाने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की गई है। पहली दो अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाएं, टाटा के

साथ-साथ रिलायंस, मुंद्रा के लिए टाटा और सासन के लिए रिलायंस ने पीपीए के संशोधन प्रक्रिया के माध्यम से अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। जब हम पीपीए में संशोधन की बात करते हैं तो परियोजना की समय पर स्थापना न कर पाने के कारण इसमें वित्तीय व्यवधान पैदा होने लगता है इसलिए उन्होंने इस संबंध में अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। टाटा ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए कहा है कि कम से कम दो यूनिटें 17 माह की पूर्वावधि से काम करेंगी और रिलायंस के मामले में 3 वर्ष की पूर्व अवधि की प्रतिबद्धता जाहिर की गई है। इन परियोजनाओं में से प्रत्येक की कम से कम दो यूनिटें 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में ही स्थापित हो जाएंगी जिससे 2920 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि होगी। इस प्रकार यहां तक कि यदि योजनागत क्षमता अभिवृद्धि के लक्ष्य से हम काफी पीछे रहते हैं तो इसे उस प्रकार की पूर्वावधि का लाभ मिलेगा अन्यथा तेजी से कार्य पूर्ण करने के लिए पर्याप्त समय शेष रहेगा, भले ही कार्य प्रारंभ होने में कुछ बिलंब क्यों न हो। इसलिए हम यह अपेक्षा नहीं करते हैं कि वास्तविक क्षमता अभिवृद्धि हमारी योजना से बहुत अलग होगी।

वक्ता नं. 1: श्रीमान जी, एक प्रश्न और, जिस 80,000 के बारे में हम बात कर रहे हैं इसमें से वित्त पोषण व्यवस्था में शामिल होने पर हमें क्या हिस्सा मिलेगा? यह आवश्यक नहीं है कि हमें पूरा हिस्सा मिले परंतु हमारी स्थिति समूह के भागीदार अथवा किस रूप में होगी?

सतनाम सिंह: जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टाटा की मुंद्रा परियोजना के अलावा हम लगभग सभी परियोजनाओं में भागीदार हैं। इस प्रकार, यह प्रश्न ही नहीं उठता कि हम भारत सरकार के सभी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमों को हासिल करने में सफल न हों जब तक कि एक्सपोजर संबंधी कोई मुद्दा सामने नहीं आता है; अन्यथा हमने ऐसी सभी क्षमता अभिवृद्धि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का विकल्प खुला रखा है। ऐसी कोई भी परियोजना विशेष रूप से बड़े आकार वाली, लार्ज – टिकिट परियोजनाएं नहीं हैं जो हमारी सहायता के बिना वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हों। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारा निबल मूल्य एसबीआई, आईसीआईसीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे 4 से 5 शीर्षस्थ बैंकों को छोड़कर ज्यादातर बैंकों की तुलना में कम से कम तीन गुना है। और विद्युत परियोजनाओं के लिए पूंजी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कंपनियों को हमारे जैसे संस्थानों के समक्ष पहल करना आवश्यक है।

वक्ता नं. 2: इसके क्या कारण हैं कि हमारे ज्यादातर ऋणग्राही राजकीय यूनिटें हैं? यह उत्पादन प्रोफाइल के कारण नहीं हैं, अतः इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है कि हमारे ज्यादातर ऋणग्राही राज्य क्षेत्र की यूनिटें हैं?

प्रबंधन: ठीक है, जहां तक आप सभी को जानकारी होगी कि नब्बे के दशक तक विद्युत परियोजनाएं राजकीय विद्युत क्षेत्र के अधिकार में आती थीं और कुछ लाइसेंस धारक कुछ केंद्रीय

क्षेत्र की परियोजनाएं हुआ करती थीं जो कि सभी राज्य, केंद्र अथवा संयुक्त क्षेत्र से जुड़ी होती थीं। केवल नब्बे के दशक में ही विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र का प्रवेश हुआ और उस समय यद्यपि निजी क्षेत्र को विद्युत परियोजनाओं की मंजूरी और आबंटन के लिए बहुत उत्साह दिखाया गया था परंतु बाद में यह महसूस किया गया कि यह कोई आसान कार्य नहीं है और इसी वजह से इस दिशा में बिलंब हुआ है। केवल वर्ष 2004-05 से निजी क्षेत्र में पुनः रूचि पैदा हुई है परंतु दोनों के बीच महत्वपूर्ण अंतर बनाए रखने के लिए उचित दिशानिर्देश तैयार किए गए और मंजूरीयों के मामले में भी यह अंतर देखने को मिलता है। परंतु संपूर्ण विद्युत बाजार की तुलना में प्रतिशत के संदर्भ में अंतर करने के लिए उन्हें काफी समय लगेगा, हो सकता है कि इसमें 3 से 4 वर्ष का समय लग जाए। परंतु मैं आपको यह जानकारी देता हूँ कि जो भी प्रतिशत निर्धारित किया जाएगा उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि का प्रावधान होगा। मैं निजी क्षेत्र की कुल उत्तरोत्तर सहभागिता की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में 9 प्रतिशत थी और 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसे बढ़ाकर 21 प्रतिशत और 12वीं पंचवर्षीय योजना में 63 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार, वास्तव में 12वीं पंचवर्षीय योजना में ही इस प्रतिशत का सही अंतर दिखाई देगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना में निजी क्षेत्र के लिए 21 प्रतिशत की उत्तरोत्तर वृद्धि का प्रावधान किया गया है, परंतु संपूर्ण आधार पर इससे बहुत अधिक अंतर नहीं पड़ने वाला है, हालांकि यह संख्या आकर्षक होगी। और इसलिए यदि राज्य / केंद्र / संयुक्त क्षेत्र की कंपनियां सामने आती हैं तो उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

वक्ता नं. 3: श्रीमान जी मेरे दो प्रश्न हैं, एक तो यह कि आपने अपने परामर्श कारोबार को इस वर्ष से पुनः मर्ज कर दिया है?

सतनाम सिंह: हां, आप ठीक हैं।

वक्ता नं. 3: और आपने इस वर्ष के वित्तीय विवरणों में अन्य प्रचालन आय नहीं दर्शायी है, अतः मैं यह केवल यह जानना चाहता हूँ कि उस स्रोत से होने वाली आय क्या है?

सतनाम सिंह: गत वर्ष पट्टे (लीज), यूएमपीपी, परामर्श, आय कर रिफण्ड आदि से होने वाली आय 71 करोड़ रूपए थी, इस वर्ष यह 66 करोड़ रूपए है। और जहां तक पीएफसी कंसल्टिंग का संबंध है, तो इसका कर पश्चात लाभ 21 से 22 करोड़ रूपए की तुलना में लगभग 10 करोड़ रूपए है।

वक्ता नं. 3: ठीक है श्रीमान जी अभी आपने इस बात का उल्लेख किया कि आपकी एपीडीआरपी मंजूरी और संवितरण पहले ही हो गए हैं, ऐसी स्थिति में आपको वर्तमान वित्त वर्ष 2010 के लिए किसी स्कीम विशेष से शुल्क आधारित आय के साथ साथ ऋणों के संवितरण से कौन – कौन से अवसर प्राप्त हो सकते हैं?

सतनाम सिंह: हमें 25 करोड़ रूपए की शुल्क आधारित आय हुई है। यह 52000 करोड़ रूपए की परियोजना है और इसमें हमारी आय स्वीकृत ऋणों का लगभग 1 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।

वक्ता नं. 3: ठीक है, ऋणों के संवितरण के संबंध में आपको क्या लगता है कि विशेष रूप से एपीडीआरपी के लिए यह वर्ष कैसा रहने वाला है?

सतनाम सिंह: मुझे लगता है कि विश्लेषकों के साथ बैठक के दौरान मुझे इस संबंध में कोई मार्गदर्शन नहीं करना चाहिए। इसके बावजूद भी यदि आप जानना चाहते हैं तो मैं केवल आपको संवितरण के संदर्भ में समझौता ज्ञापन के लक्ष्य की जानकारी दे सकता हूँ, यह लगभग 2300 करोड़ रूपए है और इसमें से एपीडीआरपी की हिस्सेदारी लगभग 1900 करोड़ रूपए की है।

वक्ता नं. 3: आपका बहुत – बहुत धन्यवाद।

वक्ता नं. 4: रिलायंस पावर की प्रगति क्या है?

सतनाम सिंह: ठीक है, रिलायंस पावर को शासन परियोजना के लिए हमने 1770 करोड़ रूपए स्वीकृत किए हैं और उनकी कृष्णापट्टनम परियोजना के लिए प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है, वास्तव में, हम कृष्णापट्टनम परियोजना के लिए संपूर्ण कर्ज की व्यवस्था के संबंध में आईडीबीआई बैंक के साथ बातचीत कर रहे हैं। जहां तक प्रगति का संबंध है, तो अभी मैं आपको केवल यह बता सकता हूँ कि इस माह वित्तीय समाप्ति की संभावना है। परंतु यह प्रश्न आपको रिलायंस पावर से पूछना चाहिए न कि मुझसे!

वक्ता नं. 4: ऋणदाता के रूप में आपको यह जानना चाहिए...

सतनाम सिंह: हाँ, परंतु मैं आपको आधिकारिक रूप से यह नहीं बता सकता हूँ कि इसकी प्रगति जारी है; मैं आपको केवल अपनी सूचना दे सकता हूँ परंतु यदि निष्पादन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आपको यह प्रश्न रिलायंस पावर से पूछना चाहिए।

वक्ता नं. 4: धन्यवाद श्रीमान जी।

वक्ता नं. 5: जब आप विद्युत परियोजनाओं के लिए कोई धनराशि उधार देते हैं तो ऋण स्वीकृत करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त करने से पहले आप किन महत्वपूर्ण चर (वेरिएबल) को ध्यान में रखते हैं और दूसरे आपकी इक्विटी अथवा परियोजना आईआआर, जिनके लिए संभवतः आप कोई ऋण स्वीकृत करते हैं, के संदर्भ में आंतरिक लक्ष्य क्या हैं?

सतनाम सिंह: ठीक है, मुझे खुशी है कि कुछ लोग आधारभूत प्रश्न भी पूछते हैं। हमारे पास दोहरी मूल्यांकन प्रणाली है। हम प्रमोटर का विश्लेषण इस बात को ध्यान में रखते हुए उनका मूल्यांकन करने के लिए करते हैं कि क्या वे विद्युत परियोजनाओं के लिए आवश्यक इक्विटी अंशदान करने में सक्षम हैं और क्या उनके पास ऐसी परियोजना क्रियान्वित करने की योग्यता और क्षमता मौजूद है, इन बातों को हम प्रमोटर के विश्लेषण के दौरान ध्यान में रखते हैं। परंतु जहां तक परियोजना विश्लेषण का संबंध है, हम बेंचमार्क लागत देखते हैं, हम यह देखते हैं कि आईआरआर हमारे मानकों की तुलना में कम न हों... अर्थात् आईआरआर कम से कम 12 प्रतिशत होना चाहिए। हम इस बात को भी ध्यान में रखते हैं कि क्या परियोजना के लिए सभी स्वीकृतियां मिल गई हैं अथवा यदि नहीं मिली हैं तो इन स्वीकृतियों की स्थिति क्या है; चाहे यह पर्यावरण स्वीकृति अथवा कोयला संपर्क अथवा रक्षा स्वीकृति या अन्य आवश्यक स्वीकृतियां कोई भी क्यों न हों; यदि इसमें वन स्वीकृति शामिल है तो यहां तक कि इसे भी ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा, हम यह भी देखते हैं कि विद्युत की बिक्री के संदर्भ में करार, ईंधन की खरीद के संबंध में करार, जहां भी आवश्यक हों, कि प्रक्रिया किस चरण में है; इसके अलावा पावर प्लांट का प्रचालन कौन करने वाला है, क्या प्रमोटर के पास प्लांट के प्रचालन की क्षमता स्वयं मौजूद है अथवा वह इस कार्य के लिए कोई स्थापित एवं प्रतिष्ठि ओ एंड एम संविदाकार की सेवाएं लेने वाला है? इसके अलावा, इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है कि परियोजना में किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाना है और परियोजना संबंधी उपस्करों की खरीद घरेलू अथवा अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं द्वारा की जानी है? इन उपस्करों के प्रचालन के लिए दक्षता संबंधी मानदंड क्या हैं, इस बात को ध्यान में रखा जाता है? उदाहरण के लिए, वर्तमान में हम सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी की, जहां 500 मेगावाट क्षमता वाली विद्युत परियोजनाओं और इसके आसपास की विद्युत परियोजनाओं के लिए तुलनात्मक रूप से थर्मल दक्षता 7 प्रतिशत से 8 प्रतिशत तक अधिक होती है, तलाश कर रहे हैं। यह तो संक्षिप्त जानकारी है परंतु इससे संबंधित मानकों की सूची बड़ी लंबी है।

वक्ता नं. 5: क्या आप उन परियोजनाओं के बीच कोई भेद अथवा विभेद करते हैं जो उदाहरण के लिए चीन के उपस्करों अथवा कोई अन्य उपस्करों का उपयोग करते हैं?

सतनाम सिंह: हां, निश्चित ही जब हम प्रौद्योगिकी और आपूर्तिकर्ताओं को ध्यान में रखते हैं तो हम उनके आपूर्तिकर्ताओं पर भी विचार करते हैं और इस बात को भी ध्यान रखते हैं कि उनके लिए वित्तीय मानदंड क्या होंगे। यदि आपका प्रश्न यह है कि चीन के उपस्कर स्वीकार्य हैं अथवा नहीं, तो मेरा उत्तर यह है कि भारत सरकार ने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण से इस संबंध में एक अध्ययन करने के लिए कहा है और उन्होंने 600 मेगावाट क्षमता वाली यूनिटों के लिए अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत भी कर दी है जिसमें उन्होंने यह उल्लेख भी किया है कि 600 मेगावाट तक का निष्पादन विश्व में किसी अन्य उत्पाद के समतुल्य है और जहां तक 600

मेगावाट से अधिक आकार वाली यूनिटों का सवाल है तो हमारी टीम अभी हाल ही में चीन वापस लौटी है और वे इस संबंध में बहुत बहुत प्रसन्न हैं, यद्यपि उन्होंने अभी तक आधिकारिक रूप से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

वक्ता नं. 6: 23000 करोड़ रूपए की संवितरण का आपका लक्ष्य वित्त वर्ष 2009 में आपके द्वारा संवितरित किए गए 21000 करोड़ रूपए की तुलना में थोड़ा कम प्रतीत होता है और इसके अलावा वित्त वर्ष 2008 में आपने लगभग 70000 करोड़ रूपए की राशि मंजूर की जिसमें से मेरे साथ साथ आपको भी लगता होगा कि ज्यादातर वित्त वर्ष 2010 और वित्त वर्ष 2011 में आएगी, क्या आप इसे स्पष्ट कर सकते हैं?

सतनाम सिंह: हम चाहते हैं कि विश्लेषक अपना दिमाग लगाएं। मैंने आपको यह भी बताया है कि हमारे पास 120000 करोड़ रूपए की बकाया स्वीकृतियां हैं जो अलग अलग परियोजनाओं के विभिन्न चरणों पर आधारित हैं, उनके सापेक्ष संवितरण की समस्याओं को हल किया जाएगा और नई परियोजनाओं के लिए संभवतः 60000 करोड़ रूपए की राशि निर्धारित की जाएगी और यदि दोनों को सम्मिलित कर दिया जाता है तो कितनी धनराशि का संवितरण किया जाएगा इसका अनुमान विश्लेषक को लगाना चाहिए। परंतु जो बात मैंने आपको बतायी है वह भारत सरकार के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन (एमओयू) में उल्लिखित लक्ष्य हैं और यह 23000 करोड़ रूपए है। वास्तविक रूप से हम कितना लक्ष्य हासिल कर पाएंगे इस बात का उल्लेख मैंने नहीं किया है, अतः आप देखेंगे कि हमारी पिछले निष्पादन और उपलब्धियों के आधार पर हमारे प्रति आपका दृष्टिकोण और विश्वास कैसा है।

वक्ता नं. 6: वित्त वर्ष 2010 में किस प्रकार का पुनर्भुगतान अपेक्षित है?

सतनाम सिंह: पुनर्भुगतान? हां, पुनर्भुगतान लगभग 8000 करोड़ रूपए रहने की उम्मीद है। पुनर्भुगतान से आपका आशय क्या ऋण ग्राहियों से प्राप्त भुगतान से है?

वक्ता नं. 6: हां?

प्रबंधन: हां, 7000 से 8000 करोड़ रूपए।

वक्ता नं. 7: श्रीमान जी, कम संवितरण, जो आपने समझौता ज्ञापन (एमओयू) में तालिका के रूप में दिया है का अनुवर्ती प्रश्न यह है कि क्या आपके विचार से ऐसी स्थिति तरलता की समस्याओं के कारण निर्मित हुई है जो गतवर्ष आपके समक्ष थी और क्या यह इस वर्ष अथवा वित्त वर्ष 2010 में जारी रहेगी, और इसीलिए लक्ष्य बहुत सीमित हैं?

सतनाम सिंह: मेरे दृष्टिकोण से जो बात मैंने आपके समक्ष रखी है कि तरलता की समस्या दिसंबर 2008 तक थी, उस समय बैंक-हमारे जैसे एमबीएफसी को धन उधार देने के प्रति जागरूक थे। परंतु उसके पश्चात हमारे साथ तरलता की कोई समस्या नहीं रही और हमें संसाधनों के दोहन में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। हमें जो लक्ष्य दिया गया है वह समझौता ज्ञापन का लक्ष्य है, वास्तविक उपलब्धि क्या होगी, इस संबंध में मैंने कुछ नहीं कहा है, अतः...

वक्ता नं. 7: क्या श्रीमान जी चालू वर्ष के आने वाले महीनों के दौरान आपको तरलता संबंधी किसी समस्या के आने का अनुमान है?

सतनाम सिंह: नहीं, मैंने ऐसा केवल इसलिए कहा है कि हमारे समक्ष वर्तमान में तरलता की कोई समस्या नहीं है, भविष्य के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, आप ही मुझे बताना चाहिए।

वक्ता नं. 7: श्रीमान जी, संख्याओं के संबंध में एक और स्पष्टीकरण, आपने अपने भाषण में उल्लेख किया कि आपने 253 करोड़ रूपए की विदेशी विनिमय हानियों को बुक किया था, परंतु तुलनात्मक स्लाइड जो वहां दिखाई गई थी, में विनिमय हानियां केवल 160 करोड़ रूपए दर्शायी गई थीं।

प्रबंधन: यह कर पश्चात प्रभाव है।

सतनाम सिंह: यह कर पश्चात प्रभाव है, मैंने जिसका उल्लेख किया वह सकल राशि थी।

वक्ता नं. 8: श्रीमान जी, क्या परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में कोई प्रगति हुई है?

सतनाम सिंह: जैसा आप सभी को ज्ञात है कि वर्तमान में परमाणु विद्युत परियोजनाएं न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन द्वारा की जा रही हैं जो कि नकदी की दृष्टि से संपन्न कंपनी है और चूंकि उनकी विस्तार योजनाएं पूर्व में बहुत बड़ी नहीं थी क्योंकि उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था और उन्होंने बाजार अथवा वित्तीय संस्थानों से कोई भी धनराशि उधार नहीं ली थी। अभी 1, 2, 3 सौदे किए गए हैं, और हमारी सूचना के अनुसार उनकी विस्तार योजनाओं में वृद्धि हो रही है और हम लगातार उनके संपर्क में हैं और जैसा मैंने पूर्व में भी कई फोरमों पर इस बात का उल्लेख किया है कि हम परमाणु विद्युत परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर हैं, हम इस दिशा में भी अवसरों की तलाश कर रहे हैं। जैसे ही परियोजना निधियन के लिए तैयार होती हैं हम उन परियोजनाओं को लेने का प्रयास करेंगे।

वक्ता नं. 8: श्रीमान जी, क्या इस बात की परिकल्पना करना सही होगा कि आपने जो भी समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है, उसमें परमाणु ऊर्जा क्षेत्र से कुछ भी शामिल नहीं है?

सतनाम सिंह: अगले एक वर्ष में चूंकि हमें ऐसा कोई आइडिया नहीं है कि वे इससे संबंधित कोई परियोजना प्रस्तुत कर सकेंगे, इसलिए हमने अभी इसे ध्यान में नहीं रखा है। इसमें बहुत सी अन्य बातें शामिल होंगी। हो सकता है कुछ विकासकर्ताओं ने हमारे साथ अभी बातचीत न की हो, उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा क्षेत्र के विकासकर्ता, परंतु हमारी नीति सभी के लिए मुक्त रूप से खुली है, ऐसे भी लोग हैं जो इस बारे में सोच रहे हैं तथा इस प्रकार की कोई परियोजना तैयार करने के लिए बहुत अधिक समय आवश्यक नहीं है और न ही नवीकरणीय परियोजना तैयार करने में कोई अधिक समय लगना है। इस प्रकार जैसे ही नई परियोजनाएं आएंगी, उनके लिए त्वरित संवितरण संभावित है।

वक्ता नं. 8: श्रीमान जी, एक छोटा सा प्रश्न, पुनर्गठित एपीडीएस जिसके लिए आप नोडल एजेंसी हैं, इससे आपको 1 प्रतिशत का शुल्क कहां से प्राप्त होगा, श्रीमान जी यह परियोजना कितने वर्ष के लिए वैध है?

सतनाम सिंह: यह 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए है। आप इसे 3 वर्ष मान सकते हैं। हां कुनाल?

कुनाल: श्रीमान जी, 57000 करोड़ रूपए की मंजूरीयों में से मुझे लगता है कि हमने 10000 करोड़ रूपए का कारपोरेट स्तर का ऋण एनटीपीसी को स्वीकृत किया है।

सतनाम सिंह: यह ठीक है,

कुनाल: इसमें संभावित गिरावट क्या होगी? क्या यह 23000 करोड़ रूपए के निर्धारित लक्ष्य में शामिल है?

सतनाम सिंह: न केवल एनटीपीसी, बल्कि सभी मंजूरीयों पर संवितरण की अनुसूची के आधार पर विचार किया गया है जिसके बारे में हमने सभी विकासकर्ताओं से राय ली थी और 23000 करोड़ रूपए की संवितरण योजना में ये सभी मद शामिल हैं।

कुनाल: श्रीमान जी, सामान्यतः कारपोरेट स्तर के ऋणों के संवितरण में कितनी गिरावट होती है? हो सकता है यह परियोजना स्तर पर भी हो, आगामी पांच वर्ष के दौरान हम इस पर नजर रखेंगे ...

सतनाम सिंह: यह कारपोरेट ऋण इसलिए कहलाता है क्योंकि एनटीपीसी एक 'एएए' कंपनी है परंतु यह ऋण कुछ विशिष्ट परियोजनाओं के सापेक्ष दिया गया है अतः उन संगत परियोजनाओं की प्रगति के आधार पर आहरण अनुसूचियां तैयार की जाती हैं।

कुनाल: ठीक है, श्रीमान जी आपके विस्तार के बारे में एक और प्रश्न, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपका विस्तार 2.4 प्रतिशत के साथ सर्वश्रेष्ठ है परंतु देनदारी ढांचे को देखते हुए यह आपकी निर्धारित देनदारी के 85 अथवा 90 प्रतिशत हो सकता है और हम तिमाही दर तिमाही निधियों की लागत में 9.3 प्रतिशत से 8.8 प्रतिशत की कमी देख रहे हैं तो क्या ऐसी स्थिति में महत्वपूर्ण पुनर्भुगतान का कोई प्रावधान किया है अथवा यह भी हो सकता है कि आपने कुछ उच्च लागत वाले कर्ज का पुनर्भुगतान किया है और उसके बदले में कम लागत वाला कुछ कर्ज लिया है?

सतनाम सिंह: यह सामान्य प्रक्रिया है, हम तब ऐसा करते रहते हैं जब कभी उधार लेते समय पीएलआर का प्रावधान किया जाता है अथवा अन्य किसी ढांचे को अमल में लाया जाता है जहां बाजार के अनुरूप लागत में गिरावट होती है और किसी भी सूरत में कम ही होता है। परंतु जहां इस प्रकार का कोई साधन नहीं किया जाता है, जब कभी बाजार में नाटकीय परिवर्तन या तो ऊपर की ओर अथवा... ऊपर की ओर वृद्धि के संकेत मिलते हैं तो हम निश्चित ही नीचे की ओर नहीं देखते हैं, ऐसी स्थिति में हम लागत की कमी की संभावना से संगत संस्थानों के साथ इस मुद्दे को अवश्य उठाते हैं और यदि संगत संस्थान सहमत नहीं होते हैं तथा वैकल्पिक स्रोत से हमें कम लागत का प्रस्ताव दिया जाता है तो ऐसे ऋणों का हम पुनर्भुगतान कर देते हैं।

कुनाल: श्रीमान जी, क्या इसका कोई बड़ा प्रभाव (लैंग इफेक्ट) पड़ेगा और क्या हम इन विस्तारों को अगली दो अथवा तीन तिमाही के दौरान 2.2 से अलग प्रतिशत के सापेक्ष देख सकते हैं?

सतनाम सिंह: अपनी बात पुनः कहें, मैं इसे ठीक ढंग से सुन नहीं पाया हूँ।

कुनाल: हो सकता है यह विस्तार 2.4 प्रतिशत हो, हो सकता है कि इसका कोई बड़ा प्रभाव पड़े क्योंकि हम आपकी लब्धि में कोई बड़ी कमी नहीं देख रहे हैं, यह 11.2 प्रतिशत बनी हुई है जबकि निधियों की लागत में लगभग 50 आधार बिंदुओं की महत्वपूर्ण गिरावट हुई है। अतः हो सकता है कि यह बड़ा प्रभाव अगली दो अथवा अधिक तिमाहियों पर भी पड़े।

सतनाम सिंह: मैं भविष्य में विस्तार के संबंध में कोई संकेत नहीं देना चाहता हूँ, परंतु मैं आपको यह अवश्य बता देना चाहता हूँ कि हम अपने इस विस्तार को 2 प्रतिशत से अधिक अवश्य बनाए रखेंगे और अंतिम तिमाही के दौरान जो थोड़ा बहुत गिरावट आई है वह वास्तविक रूप से ब्याज दरें पुनः निर्धारित किए जाने के कारण ऋण की मात्रा में कमी के परिणामस्वरूप है और अंतिम तिमाही में हुई आय अपेक्षाकृत बेहतर है और इसका प्रभाव विस्तार में भी देखने को मिल सकता है। यदि अभीष्ट आंकड़ा जानना चाहते हैं, यह 53 करोड़ रूपए है। यह प्रत्येक तिमाही का आंकड़ा नहीं है, इसलिए आपको वार्षिक विस्तार 2.2 प्रतिशत अथवा अधिक रहने की बात मान लेनी चाहिए।

कुनाल: ठीक है, श्रीमान जी इस तिमाही अधिनिर्णीत तिलैया परियोजना को बुक करने से आपको शुल्क के रूप में होने वाली आय क्या होगी?

सतनाम सिंह: 15 करोड़।

कुनाल: ठीक है, धन्यवाद श्रीमान जी।

वक्ता नं. 9: आपके निजी इक्विटी कारोबार पर केवल एक प्रश्न, क्या आप अद्यतन स्थिति बता सकते हैं और कारोबार की इस दिशा में क्या हो रहा है?

सतनाम सिंह: मुझे विश्वास है कि आपको इस बात की जानकारी होगी कि विद्युत और दूरसंचार क्षेत्र में उद्यम पूंजी निधियों पर कर संबंधी कोई छूट प्राप्त नहीं है और इसलिए गत वर्ष हमने एक भारतीय विद्युत निधि की स्थापना का विचार बनाया था तथा इसके एक विकल्प के रूप में हमने पावर लैंडर्स क्लब की तर्ज पर एक इक्विटी कंसोर्टियम बनाने पर विचार किया था। आपको जानकारी होगी कि पावर लैंडर्स क्लब में 18 बैंक, एलआईसी और हुडको शामिल हैं और हम ऋण उधार देने के परिप्रेक्ष्य में विद्युत परियोजनाओं की राह देख रहे हैं, इसके अलावा हम कितने एक्सपोजर का लाभ ले सकते हैं क्योंकि पावर लैंडर्स क्लब के सदस्यों के साथ निबंधन और शर्तों के लेकर आम सहमति पहले ही बन गई है और हमने पावर लैंडर्स क्लब को इसका प्रस्ताव दिया है। इसी तर्ज पर हम एक कंसोर्टियम के सृजन पर विचार कर रहे हैं। हमने भारतीय विद्युत परियोजनाओं में इक्विटी निवेश के इच्छुक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों (कंपनियों) को लिखा था। इनमें से कुछ के जवाब हमें प्राप्त हुए हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम इस दिशा में काफी सकारात्मक है। निश्चित ही जैसा कि आपको ज्ञात है, इसके पश्चात बात आयी गई हो गई और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां आगे नहीं आईं और यहां तक कि घरेलू संस्थान ही इस विषय में बार बार सोचते हैं, इसीलिए इसकी तैयारी, कंसोर्टियम और मानक निबंधन और शर्तें निरूपित करती हैं अपेक्षाकृत अधिक समय लग रहा है। हालांकि हमने एक ऐसे उत्पाद के विकास के बारे में विचार किया है जो हो सकता है अबसे तीन से चार माह की अवधि में लागू किया जाए।

वक्ता नं. 9: इस प्रकार की भी चर्चाएं थीं कि पावर फाइनेंस कारपोरेशन स्वयं भी इनमें से कुछ परियोजनाओं में इक्विटी निवेश तथा एक्सपोजर कर सकता है, तो क्या इस दिशा में कोई प्रगति हुई है?

सतनाम सिंह: क्या आप अपना प्रश्न पुनः कर सकते हैं? आप किस चर्चा की बात कर रहे हैं?

वक्ता नं. 9: पावर फाइनेंस कारपोरेशन के संदर्भ में योजनाएं जिनमें पीएफसी वास्तविक रूप से प्रत्यक्ष एक्सपोजर करना चाहता है और या उसी कंसोर्टियम के एक भाग के रूप में शामिल होना चाहता है जहां आपको कुछ और निवेशक भी मिल सकते हैं, क्या उन परियोजनाओं में पीएफसी भी इक्विटी निवेशक के रूप में शामिल होगा, क्या इस संबंध में कोई विचार किया गया है? क्या ऐसा वास्तव में हो सकता है, क्या यह इसी प्रकार की संरचना है जिसके बारे में आप बता रहे थे जो आगामी 3 से 4 माह में सार्वजनिक की जाएगी।

प्रबंधन: हां, मैं इसके बारे में ही बात कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि यदि हम अपने कंसोर्टियम सदस्यों द्वारा इक्विटी में निवेश कराना चाहते हैं, हमें पहले किसकी निबंधन और शर्तों का मानकीकरण करना होगा क्योंकि वे यह जानना चाहेंगे कि उनके लिए इसमें कौन सा लाभ निहित है, अतः जब तक निबंधन और शर्तों को अंतिम रूप नहीं दिया जाता है, कंसोर्टियम गठित करना संभव नहीं होगा। इस प्रकार यह स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। हम अपनी निबंधन और शर्तें तैयार कर सकते हैं और फिर कंसोर्टियम को बता सकते हैं, तो हो सकता है कुछ सामने आएँ और कुछ लोग इससे इंकार करें और कहें कि उन्हें यह स्वीकार्य नहीं है। इस प्रकार हमने जो मसौदा तैयार किया है वह मुर्गी और अंडे जैसी बात है, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं और इन बातों पर आम राय बन जाती है तो ही आगे बढ़ा जा सकता है।

वक्ता नं. 9: ठीक है, धन्यवाद श्रीमान जी।

वक्ता नं. 10: श्रीमान जी, वास्तविक रूप से दो प्रश्न। क्या इसका कोई विशेष कारण है कि आपके संवितरण और मंजूरीयों का रूझान ज्यादातर उत्पादन परियोजनाओं की ओर रहता है न कि पारेषण से जुड़ी परियोजनाएं?

सतनाम सिंह: नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हां यदि आप आंकड़े देखेंगे तो ऐसा लगता है परंतु जहां तक पारेषण का प्रश्न है तो उनके लिए एक बड़ी कंपनी पावर ग्रिड कारपोरेशन कारोबार का संचालन करती है जो अंतर्राज्य पारेषण प्रणाली का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। उत्पादन के क्षेत्र में ऐसा कोई ढांचा उपलब्ध नहीं है। निश्चित ही एनटीपीसी जैसी कंपनी अवश्य है परंतु हमारा ध्यान उत्पादन पर आकृष्ट है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भविष्य में वितरण क्षेत्र पर भी विचार किया जाएगा, 52000 करोड़ रूपए का यह प्रयास भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। इस दिशा में आगे बढ़ने से ऐसी जड़ता नहीं रहेगी क्योंकि वितरण क्षेत्र में भी अधिक से अधिक परियोजनाएं स्वीकृत होंगी।

वक्ता नं. 10: श्रीमान जी, मैं केवल यह जानना चाहता हूँ कि इस दिशा में क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है। यहां तक कि राज्य संरचना से पारेषण के क्षेत्र में केपेक्स (सीएपीईएकस) की बड़ी मात्रा को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है और राज्य क्षेत्र की ज्यादातर कंपनियों में

वित्तीय परेशानियां भी होती हैं। क्या आप इस क्षेत्र विशेष में मंदी के कुछ संकेत देख रहे हैं और इसीलिए आप इस दिशा में अधिक आशावित नहीं हैं?

सतनाम सिंह: आप देखेंगे कि हमने पिछले वित्त वर्ष की शुरुआत में एक कार्रवाई की थी कि हमने राज्य क्षेत्र में जो भी विद्युत परियोजनाएं मंजूर की हैं तो क्या उनके बाद इन परियोजनाओं के स्थापना के समय से ही उनकी अपनी संगत पारेषण लाइनें हैं अथवा नहीं और परिणाम सकारात्मक रहा। सभी कंपनियों ने पारेषण लाइनों के लिए इस प्रकार से योजना बनाई थी कि वे स्थापित उत्पादन स्टेशनों से विद्युत प्राप्त करने और आगे पारेषित करने में सक्षम होंगे। इस प्रकार इस संबंध में कोई समस्या नहीं है।

वक्ता नं. 10: श्रीमान जी, वास्तविक रूप से दो प्रश्न, एक प्रश्न यह है कि क्या ऐसी कोई विशिष्ट सीमा निर्धारित की गई है जिस तक आप किसी विशेष कारपोरेट समूह को एक्सपोजर प्रदान कर सकते हैं? मैं विशेष रूप से रिलायंस पावर के मामले में जानना चाहता हूँ क्योंकि उनके पास अब 3 यूएमपीपी हैं, क्या इसकी कोई विशिष्ट सीमा निर्धारित है?

सतनाम सिंह: मैंने अपनी प्रारंभिक चर्चा के दौरान ही आपको बताया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने बहुत ही श्रेणीकृत ढंग से बताया है कि जहां तक निजी क्षेत्र का संबंध है, हमें सभी संस्थानों के लिए मानक शर्तों का अनुपालन करना अपेक्षित है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाती है और वे अवसंरचना क्षेत्र में वित्त पोषण से संबंधित हैं। इस प्रकार यह सीमा प्रत्येक परियोजना के निबल मूल्य के 20 प्रतिशत तक निर्धारित है इसका आशय यह है कि एकल ऋणग्राही को परियोजना लागत की 20 प्रतिशत और सामूहिक रूप से 35 प्रतिशत की सीमा निर्धारित है।

वक्ता नं. 10: क्या आपने अभी तक किसी मर्चेट पावर प्लांट के लिए मंजूरी दी है?

सतनाम सिंह: नहीं, वास्तविक रूप से नहीं, परंतु हमारे द्वारा पहले से वित्त पोषित विद्युत परियोजनाओं में से कुछ के पास अतिरिक्त रूप से मर्चेट पावर प्लांट उपलब्ध है, जिसके परिणामस्वरूप वे कंपनियां अच्छा खासा धन अर्जित कर रही हैं। उदाहरण के लिए जिंदल की बिलारी परियोजना, हमने पुनः वित्त पोषण किया है, पूर्व में इसे आईसीआईसीआई द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी, हमने इसे पांच वर्ष पहले वित्तीय सहायता दी थी और इस परियोजना के पास एक विकल्प उपलब्ध है कि विद्युत के एक भाग की बिक्री मर्चेट आधार पर की जा सकती है। वे भारी मात्रा में धन अर्जित कर रहे हैं।

वक्ता नं. 10: क्या उस मर्चेट क्षमता की कोई ऊपरी सीमा निर्धारित है जिस पर आप मंजूरी का अनुमोदन करते समय सामान्यतः विचार करते हैं?

सतनाम सिंह: नहीं, किसी परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान करने का हमारा निर्णय इस पर आधारित नहीं होता है। यह परियोजना की व्यवहार्यता पर आधारित होता है। अब व्यवहार्यता की बहुत सी विशेषताएं – टैरिफ आदि हैं। माना कि यदि कोई 9 रूपए टैरिफ पर मर्चेट पावर प्लांट की स्थापना करता है तो ऐसी कंपनी अथवा व्यक्ति को हम वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करेंगे क्योंकि हम यह भलीभांति जानते हैं कि यह टैरिफ व्यवहार्य नहीं है अर्थात् इसे जारी नहीं रखा जा सकता है। परंतु उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति 1 रूपए टैरिफ पर मर्चेट पावर प्लांट लगाता है तो ऐसी स्थिति में क्रेडिट संबंधी कोई जोखिम नहीं है और ऐसी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है। इसके अलावा, यदि कोई अनुपयोगी डेवलपर मर्चेट पावर प्लांट लगाता है, हम इस पर विचार नहीं करेंगे। परंतु टाटा पावर जैसी कोई कंपनी यदि मर्चेट पावर प्लांट लगाती है अथवा ऐसी कंपनी जिसे विद्युत क्षेत्र का पहले अनुभव प्राप्त है अपने यहां मर्चेट पावर प्लांट की स्थापना करती हैं तो निश्चित ही पावर फाइनेंस कारपोरेशन द्वारा उनके वित्त पोषण पर अवश्य विचार किया जाएगा।

वक्ता नं. 11: श्रीमान जी, वित्त वर्ष 2010 में हम कितनी यूएमपीपी आबंटित करने वाले हैं?

सतनाम सिंह: मैंने अपनी आरंभिक चर्चा के दौरान ही आप लोगों को बताया था कि 3 यूएमपीपी के लिए आरएफक्यू आगामी 3 से 4 माह में जारी कर दिए जाएंगे। इनमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तमिलनाडु की यूएमपीपी शामिल हैं। यह पहला लक्ष्य (माइलस्टोन) है, जिसके पश्चात हमें प्रगति करनी है और इसके बाद ही हम इस आशय के संकेत दे सकते हैं। यदि आप मानकों पर नजर डालेंगे तो ये तीनों परियोजनाएं जुलाई अगस्त से कार्रवाई प्रारंभ किए जाने की स्थिति में इस वित्त वर्ष की समाप्ति तक अभिनिर्णीत हो जानी चाहिए।

वक्ता नं. 11: श्रीमान जी, क्या रिलायंस पावर आगे इस यूएमपीपी में बोली लगाने के लिए पात्र है?

सतनाम सिंह: हां, वर्तमान दिशा-निर्देशों के आधार पर वे बोली लगाने के लिए पात्र हैं।

वक्ता नं. 11: धन्यवाद श्रीमान जी।

वक्ता नं. 12: आज की तारीख में आपकी ऋणबही में कितने ऋण फ्लोटिंग आधार पर और कितने ऋण फिक्स्ड आधार पर हैं?

सतनाम सिंह: फिक्स्ड रेट और फ्लोटिंग रेट – ऋणबही? मुझे लगता है कि लगभग 17 प्रतिशत फिक्स्ड और 83 प्रतिशत फ्लोटिंग आधार पर हैं, परंतु उसमें से 14 प्रतिशत ऐसे ऋण हैं जिनका दर निर्धारण 10 वर्ष में किया जाना है और 65 प्रतिशत ऐसे ऋण हैं जिनकी दरें 3 वर्ष

में पुनः निर्धारित की जाती हैं।

वक्ता नं. 12: और उधारियों के संबंध में स्थिति क्या है?

सतनाम सिंह: उधारियों के संबंध में 15 प्रतिशत फ्लोटिंग और 85 प्रतिशत फिक्स्ड।

वक्ता नं. 12: धन्यवाद श्रीमान जी, क्या आप यह जानकारी दे सकते हैं कि आपके ऋणबही में कितने ऋणों का पुनर्मूल्यांकन अगले वर्ष की समाप्ति पर किया जाएगा और उसकी संभावित दर क्या होगी?

सतनाम सिंह: पुनर्मूल्यांकन मुझे लगता है कि लगभग 7000 से 8000 करोड़ रूपए के ऋणों का किया जाएगा। परंतु जैसा आप जानते हैं कि अगले वित्त वर्षों में ब्याज के अंतर की जानकारी नहीं होगी क्योंकि अगले वर्ष ऐसे ऋणों का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा जिनका संवितरण वर्ष 2006 07 में किया गया था। इस प्रकार, वर्ष 2006 07 की उधारी दरें और 2009 10 की उधारी दरें लगभग समान हैं और उनमें मामूली अंतर है। इस प्रकार अगले वित्त वर्ष में इसे कोई बड़ी आय नहीं होने वाली है।

वक्ता नं. 12: श्रीमान जी, विदेशी विनिमय के क्षेत्र में उधारियों के लिए कितना एक्सपोजर होगा?

सतनाम सिंह: लगभग 520 मिलियन की कुल बकाया राशि में से 245 से 246 मिलियन डॉलर के समतुल्य राशि शेष है। मेरा आशय यह है कि इतनी राशि हैज नहीं की गई है। लगभग 520 मिलियन डॉलर के समतुल्य कुल बकाया राशि में से 246 मिलियन डॉलर हैज नहीं की गई है। इस 246 मिलियन डॉलर पर ही हमने 253 करोड़ रूपए की हानि बुक की है और केवल लगभग 70 मिलियन डॉलर की राशि का मोचन अनुमानतः जुलाई और अगस्त में किया जाएगा। उसमें से 80 मिलियन डॉलर का मोचन 2017 में होगा। इस प्रकार यदि वास्तविक रूप से कोई भी हानि बुक की जाती है तो निश्चित ही 31 मार्च तक हमने 51.45 की हानि बुक की है। इसमें पहले ही लगभग 49 आधार बिंदुओं की कमी हुई है, इस प्रकार आज की तारीख में हमें पहले से ही इस मद में लाभ हुआ है। इस प्रकार हम देखेंगे कि 30 जून और फिर जुलाई – अगस्त में क्या होगा जब वास्तविक मोचन किया जाएगा।

वक्ता नं. 1: एक निश्चित स्तर तक इसको बनाए रखने अथवा किसी अन्य प्रयोजन क्योंकि इसमें पहले ही 230 करोड़ रूपए की बड़ी राशि निहित है, के लिए दिमाग में किसी जोखिम प्रबंधन घटक को रखते हुए क्या आपने इस बारे में कुछ योजना बनाई है ताकि यह हानि 300, 400 करोड़ रूपए से आगे न जा सके, ऐसी स्थिति में क्या आप इसे हैज करने के बारे में सोच रहे हैं अथवा आपके दिमाग में इसका कोई अन्य उपाय है?

सतनाम सिंह: आप देखेंगे कि इस प्रकार की अनुमति के लिए किसी भी अभीष्ट आंकड़े का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसी स्थिति में ऋण की औसत दर, विदेशी मुद्रा उधारी के लिए उधारी लागत की दर आदि विचारणीय पहलू होते हैं। क्या यहां तक कि इस प्रकार की हानि जो वैकल्पिक उधारी लागत के समतुल्य है और मैं आपके साथ यह बात साझा कर सकता हूँ कि इसकी तुलना की जा सकती है, यह लगभग 8 बिंदु प्रतिशत के आसपास है, यहां तक कि बुकिंग के बाद ही ऐसी उच्च लागत जैसा आपको ज्ञात है कि एवरेशन हुआ करती है। कोई भी मुद्रा में इस दर से उतार चढ़ाव नहीं होता है जितना पिछले 6 माह में भारतीय रूपए का मूल्यहास हुआ है। इस प्रकार यह एक एवरेशन है, इसको ठीक किया जाएगा, इस बात के संकेत मिल चुके हैं इसलिए हम इसके बारे में बहुत अधिक चिंतित नहीं हैं।

वक्ता नं. 12: धन्यवाद श्रीमान जी।

वक्ता नं. 13: श्रीमान जी, आपने एपीडीआरपी योजना के बारे में चर्चा की कि निष्पादन संतोषजनक होने की स्थिति में 50 प्रतिशत ऋण को अनुदान में परिवर्तित कर दिया जाएगा। यह परिवर्तन कैसेट हो सकता है? क्या इसका आशय यह है कि उन्हें ब्याज में छूट का लाभ दिया जाएगा अथवा मूलधन के पुनर्भुगतान में कोई छूट दी जाएगी?

सतनाम सिंह: ऋण के अनुदान में परिवर्तन का वास्तविक आशय ऋण में छूट से है; ऐसी स्थिति में ऋण का पुनर्भुगतान नहीं किया जाता है।

वक्ता नं. 13: ऐसी स्थिति में क्या कंपनी को वास्तविक रूप से सरकार द्वारा उसकी क्षतिपूर्ति की जाती है?

सतनाम सिंह: निश्चित! हम अनुदान प्रदान नहीं कर सकते हैं, अन्यथा मुझे यह कहना पड़ेगा कि हम अनुदान उपलब्ध कराने वाले हैं! अनुदान राशि भारत सरकार से प्राप्त होगी इसीलिए मैंने कहा कि 52,000 करोड़ रूपए में से 32,000 करोड़ रूपए अनुदान है। परंतु प्रारंभ में चूंकि यह ऋण के रूप में दिया जाएगा, अतः हम इसमें तब तक ब्याज अर्जित करेंगे जब तक इसे अनुदान में परिवर्तित नहीं कर दिया जाता है। हम अनुदान का प्रस्ताव नहीं दे सकते हैं, आप हमें नहीं छोड़ेंगे।

वक्ता नं. 14: श्रीमान जी, इस तिमाही में आपकी कर्मचारी लागत तुलनात्मक रूप से कम है, इसके क्या कारण हैं?

सतनाम सिंह: क्या यह वाकई कम है? मुझे लगता है कि यह उचित है।

वक्ता नं. 14: मेरा आशय पिछले वर्ष की पूर्ववर्ती तिमाही से तुलनात्मक रूप से है...

सतनाम सिंह: यह केवल किसी विशेष तिमाही... चौथी तिमाही में किए गए प्रावधान के कारण हो सकता है। क्योंकि उस दौरान हमने 1900 करोड़ रूपए का प्रावधान किया था। पहली तिमाही में यह 3 करोड़ रूपए, दूसरी तिमाही में 1.98 करोड़ रूपए, तीसरी तिमाही में 1.99 करोड़ रूपए था। परंतु जो अंतर दिखाई दे रहा है वह परामर्श संबंधी कार्य को पीएफसी कंसल्टिंग के साथ डी मर्ज किए जाने के परिणामस्वरूप है और ऐसे कर्मचारी जिन्हें पिछली बार पावर फाइनेंस कारपोरेशन के रोल में बुक किया गया था, चूंकि उन लोगों को पावर फाइनेंस कारपोरेशन कंसल्टिंग लि. में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था, अतः उनका हिस्सा अब सीधे कंसल्टिंग संबंधी कारोबार में बुक किया जा रहा है।

वक्ता नं. 14: ठीक है। श्रीमान जी क्या आपने डीटीएल संबंधी प्रावधानों पर आईसीएआई की इस अधिसूचना के बारे में सुनाओ है?

सतनाम सिंह: मुझे लगता है कि मैंने इस बात का उल्लेख काफी समय पहले किया था कि अप्रैल 2007 में हमें आईसीएआई से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें उल्लेख किया गया था कि यह पावर फाइनेंस कारपोरेशन के प्रतिवेदन पर आधारित है; हमने अनुच्छेद 22 में संशोधन करने का निर्णय किया है ताकि पीएफसी को कोई भी आस्थगित कर देयता सृजित नहीं करनी पड़ेगी। अब यह देश का एक प्रमुख संगठन है, चाटर्ड एकाउन्टेंट इंस्टिट्यूट ने दो वर्ष पहले ऐसी अधिसूचना जारी की थी और अभी इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, परंतु हमारी सूचना के अनुसार अभी इस पर बात करना जल्दबाजी होगी क्योंकि औपचारिक निर्णय किसी भी दिन आ सकता है।

वक्ता नं. 15: श्रीमान जी एक प्रश्न मेरी ओर से, मेरा प्रश्न यह है कि ऋणबही का कितना हिस्सा आज भी ऐस्क्रो मैकेनिक्स द्वारा बैग किया जाता है और दूसरा प्रश्न यह है कि ऋणबही का कितना हिस्सा राज्य सरकार द्वारा अभी भी गारंटी है?

सतनाम सिंह: ऐस्क्रो संबंधी अपेक्षाएं पुरानी स्थितियों के अनुरूप हैं। राज्यों की ऐस्क्रो अपेक्षा भी पूर्ववर्ती स्थिति है और निजी क्षेत्र के लिए जैसा आप जानते हैं कि इसके लिए टीआरए व्यवस्था वैकल्पिक रूप से प्रयोग में लाई जा सकती है। जहां तक राज्य सरकार की गारंटी द्वारा समर्थित ऋणों का संबंध है, जो मुझे लगता है कि आपका दूसरा प्रश्न है, यह 30 प्रतिशत है। 25 प्रतिशत वास्तविक रूप से क्योंकि इस स्थिति में आगे बढ़ने पर राज्य गारंटी देकर अपने स्वयं के मार्ग में अवरोध पैदा करते हैं और विद्युत क्षेत्र में सुधार किया गया है, क्रेडिट संबंधी जोखिम में कमी हुई है, अब इस प्रकार की ऐसी कोई अपेक्षाएं नहीं हैं। हम परिसंपत्तियों पर प्रभार के

आधार पर निधियन कर रहे हैं ताकि संपूर्ण प्रतिशत में कमी आ सके।

वक्ता नं. 15: श्रीमान जी इस अंतिम चौथी तिमाही में क्या आपको स्मरण है कि उत्तरोत्तर विस्तार क्या है?

सतनाम सिंह: चौथी तिमाही में यह 2.42 है।

वक्ता नं. 15: श्रीमान जी, मेरा मानना है कि यह उत्कृष्ट विस्तार था?

सतनाम सिंह: यह उत्कृष्ट विस्तार नहीं है। मैंने आपको यह भी बताया है कि ऋणों की बड़ी मात्रा ब्याज दर के पुनर्निधारण हेतु उपलब्ध है और यह कि इसका आंकड़ा 53 करोड़ रूपए है। इसी के परिणामस्वरूप इस प्रकार का विस्तार हुआ है। अतः मैंने यह भी उल्लेख किया है कि आपको तिमाही विस्तार के बजाय वास्तविक विस्तार को देखना चाहिए। किसी विश्लेषक की नजर से देखें तो यह एवरेशन है। चूंकि हमें 53 करोड़ रूपए की ब्याज रहित आय नहीं होने वाली है, अतः इसमें आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं।

वक्ता नं. 15: अतः इसका आशय यह है कि चौथी तिमाही में उत्तरोत्तर विस्तार लगभग 2 प्रतिशत अथवा उसके आसपास की रेंज में था, यह बहुत अधिक नहीं था।

सतनाम सिंह: वार्षिक विस्तार को आधार माना जाए।

वक्ता नं. 15: ठीक है। आपको धन्यवाद।

सतनाम सिंह: अन्य कोई बात, कोई व्यक्ति और कुछ पूछना चाहता है?

वक्ता नं. 16: श्रीमान जी, संवितरण पर पुनः आते हुए 23,000 करोड़ रूपए का लक्ष्य एक उत्कृष्ट रेटिंग वाला लक्ष्य है अथवा यह कोई आधारभूत लक्ष्य?

सतनाम सिंह: उत्कृष्ट श्रेणी।

वक्ता नं. 16: ठीक है। आपको धन्यवाद।

सतनाम सिंह: किसी भी व्यक्ति ने सार्वजनिक क्षेत्र में आने वाली दिमागी शक्ति के बारे में चर्चा नहीं की है! आप सभी क्षयण दर के बारे में बहुत चिंतित थे, मेरा मानना है कि अब आपको क्षयण दर के बारे में अधिक समय तक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है! ठीक है यदि अब और कोई प्रश्न नहीं है तो हम आज की बैठक के समापन की घोषणा कर सकते हैं। सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।